भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 994

10 फरवरी, 2023 को उत्तरार्थ

विषय: कृषि के कार्यों में लगे व्यक्तियों द्वारा आत्महत्या किया जाना

994. श्री मल्लिकार्जुन खरगे:

क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान वर्ष के लिए अनंतिम आंकड़ों सहित विगत पांच वर्षों के दौरान कृषि क्षेत्र में लगे हुए कितने व्यक्तियों की मौत आत्महत्या करने से हुई है, तत्संबंधी वर्ष-वार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने कृषि क्षेत्र से जुड़े उन व्यक्तियों के परिवारों को कोई मदद या सहायता प्रदान की है जिनकी मृत्यु आत्महत्या से हुई है;

(ग) यदि हां, तो विगत पांच वर्षों के दौरान वर्ष-वार संस्वीकृत धनराशि सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ड.) क्या सरकार प्रभावित परिवारों की सहायता के लिए एक समान मुआवजा नीति बनाने की इच्छुक है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

<u>उत्तर</u>

<u>कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर))</u>

(क) से (छ): गृह मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) 'भारत में दुर्घटनावश मृत्यु एवं आत्महत्याएं' (एडीएसआई) नामक शीर्षक के अपने प्रकाशन में आत्महत्याओं से संबंधित सूचना का संकलन और प्रसार करता है। एनसीआरबी ने वर्ष 2021 तक की रिपोर्ट प्रकाशित की हैं जो इसकी वेबसाइट (https://ncrb.gov.in) पर उपलब्ध हैं। एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2017, 2018, 2019, 2020 और 2021 के दौरान राज्य-वार आत्महत्या करने वाले किसानों/हलवाहों की संख्या **अनुबंध** में संलग्न है।

कृषि राज्य का विषय है, राज्य सरकारें राहत प्रदान करती हैं। तथापि, भारत सरकार उचित नीतिगत उपायों और बजटीय सहायता तथा विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के माध्यम से राज्यों के प्रयासों में सहायता करती है। खेती को अधिक लाभकारी बनाने और किसानों को आर्थिक रूप से अधिक सुरक्षित बनाने के लिए भारत सरकार की विभिन्न योजनाएं/कार्यक्रम निम्नानुसार हैं:

1. **बजट आवंटन में अभूतपूर्व वृद्धि**
   वर्ष 2013-14 में, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय (डेयर सहित) और मात्स्यिकी, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय के लिए बजट आवंटन केवल 30223.88 करोड़ रुपये था। इसे वर्ष 2022-23 में 4.59 गुना से अधिक बढ़ाकर 138920.93 करोड़ रुपये कर दिया गया है।

2. **पीएम किसान के माध्यम से किसानों को आय सहायता**
   वर्ष 2019 में पीएम-किसान योजना का शुभारंभ - यह 3 समान किस्तों में प्रति वर्ष 6000 रुपये प्रदान करने वाली एक आय सहायता योजना है। अब तक लगभग 11 करोड़ पात्र किसान परिवारों को 2.24 करोड़ रूपए से अधिक धनराशि जारी की गई है।

3. **प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई)**
   छह वर्ष - वर्ष 2016 में पीएमएफबीवाई को किसानों के लिए उच्च प्रीमियम दरों और कैपिंग के कारण बीमा राशि में कमी की समस्याओं का समाधान करने हेतु शुरू किया गया था। कार्यान्वयन के पिछले 6 वर्षों में - 38 करोड़ किसान आवेदकों को नामांकित किया गया है और 12.37 करोड़ से अधिक किसान आवेदकों (अनंतिम) के दावे प्राप्त हुए हैं। इस अवधि के दौरान किसानों द्वारा उनके प्रीमियम के रूप में लगभग 25,252 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया था जिसकी तुलना में उन्हें 1,30,015 करोड़ रुपये (अनंतिम) से अधिक के दावों का भुगतान किया गया है। इस प्रकार किसानों द्वारा भुगतान किए गए प्रत्येक 100 रुपये के प्रीमियम के लिए, उन्हें दावों के रूप में लगभग 514 रुपये प्राप्त हुए हैं।

4. **कृषि क्षेत्र के लिए संस्थागत ऋण**
   i. संस्थागत ऋण की पहुंच को वर्ष 2013-14 में 7.3 लाख करोड़ रुपये से बढ़ाकर वर्ष 2022-23 में 18.5 लाख करोड़ रुपये करने का लक्ष्य रखा गया है।
   ii. केसीसी के माध्यम से अब पशुपालन और मत्स्य पालन करने वाले किसानों को भी उनकी अल्पकालिक कार्यशील पूंजी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रति वर्ष 4% ब्याज पर रियायती संस्थागत ऋण का लाभ प्रदान किया जाता है।

iii. किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) के माध्यम से सभी पीएम-किसान लाभार्थियों को कवर करते हुए रियायती संस्थागत ऋण प्रदान करने के लिए फरवरी 2020 से एक विशेष अभियान चलाया गया है। दिनांक 23.12.2022 की स्थिति के अनुसार, इस अभियान के हिस्से के रूप में 4,49,443 करोड़ रुपये की स्वीकृत ऋण सीमा के साथ 387.87 लाख नए केसीसी आवेदनों को मंजूरी दी गई है।

5. न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को उत्पादन लागत का डेढ़ गुना तय करना -

i. सरकार ने वर्ष 2018-19 से अखिल भारतीय भारित औसत उत्पादन लागत पर कम से कम 50 प्रतिशत के प्रतिफल के साथ सभी अनिवार्य खरीफ, रबी और अन्य वाणिज्यिक फसलों के लिए एमएसपी में वृद्धि की है।

ii. धान (सामान्य) के लिए एमएसपी को वर्ष 2013-14 में 1310 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर वर्ष 2022-23 में 2040 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है।

iii. गेहूं के एमएसपी को वर्ष 2013-14 में 1400 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर वर्ष 2022-23 में 2125 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया।

6. देश में जैविक खेती को बढ़ावा देना

i. देश में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2015-16 में परंपरागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई) शुरू की गई थी। 32384 क्लस्टर गठित किए गए हैं और 6.53 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को कवर किया गया है जिससे 16.19 लाख किसान लाभान्वित हुए हैं। इसके अतिरिक्त नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत 123620 हेक्टेयर क्षेत्र कवर किया गया और प्राकृतिक खेती के अंतर्गत 4.09 लाख हेक्टेयर क्षेत्र कवर किया गया। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार और झारखंड के किसानों ने नदी जल प्रदूषण को नियंत्रित करने के साथ-साथ अतिरिक्त आय प्राप्त करने के लिए गंगा नदी के दोनों ओर जैविक खेती शुरू की है।

ii. सरकार का भारतीय सांस्कृतिक कृषि पद्धति (बीपीकेपी) योजना के माध्यम से सतत प्राकृतिक कृषि प्रणालियों को बढ़ावा देने का भी प्रस्ताव है। प्रस्तावित योजना का उद्देश्य खेती की लागत में कटौती करना, किसानों की आय में वृद्धि करना और संसाधन संरक्षण और सुरक्षित एवं स्वस्थ मृदा, पर्यावरण और भोजन सुनिश्चित करना है।

iii. पूर्वोत्तर क्षेत्र जैविक मूल्य श्रृंखला विकास मिशन (एमओवीसीडीएनईआर) शुरू किया गया है। इसके तहत 379 किसान उत्पादक कंपनियों का गठन किया गया है जिसमें 189039 किसान शामिल हैं और 172966 हेक्टेयर क्षेत्र को कवर किया गया है।

7. प्रति बूंद अधिक फसल

प्रति बूंद अधिक फसल (पीडीएमसी) योजना वर्ष 2015-16 के में शुरू की गई थी जिसका उद्देश्य सूक्ष्म सिंचाई प्रौद्योगिकियों अर्थात ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणालियों के माध्यम

से खेत स्तर पर जल उपयोग दक्षता में वृद्धि करना और उत्पादकता में वृद्धि करना है। वर्ष 2015-16 से अब तक पीडीएमसी योजना के माध्यम से 69.55 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को सूक्ष्म सिंचाई के तहत कवर किया गया है।

8. सूक्ष्म सिंचाई कोष

नाबार्ड के साथ 5000 करोड़ रुपये की प्रारंभिक निधि का एक सूक्ष्म सिंचाई कोष बनाया गया है। वर्ष 2021-22 की बजट घोषणा में इस कोष में निधियों की मात्रा को बढ़ाकर 10000 करोड़ रुपये किया जाना है। इसके तहत 17.09 लाख हेक्टेयर क्षेत्रों को कवर करने वाली 4710.96 करोड़ रुपये की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है।

9. किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) का संवर्धन

i. माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा **दिनांक 29 फरवरी, 2020 को वर्ष 2027-28** तक 6865 करोड़ रुपये के बजट परिव्यय के साथ नए 10,000 एफपीओ के गठन और संवर्धन के लिए एक नई केंद्रीय क्षेत्र की योजना शुरू की गई।

ii. दिनांक 30.11.2022 तक की स्थिति के अनुसार, नई एफपीओ योजना के तहत 4028 एफपीओ पंजीकृत किए गए हैं।

iii. दिनांक 30.11.2022 तक की स्थिति के अनुसार, 1415 एफपीओ को 53.4 करोड़ रूपए का साम्या अनुदान जारी किया गया है।

iv. दिनांक 12.12.2022 तक की स्थिति के अनुसार, 447 एफपीओ को 78 करोड़ रूपए का ऋण गारंटी कवर जारी किया गया है।

10. वर्ष 2020 में आत्मनिर्भर भारत अभियान के भाग के रूप में **राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन (एनबीएचएम)** शुरू किया गया है ताकि परागण के माध्यम से फसल उत्पादकता में वृद्धि की जा सके और आय के अतिरिक्त स्रोत के रूप में शहद उत्पादन में वृद्धि की जा सके। मधुमक्खी पालन क्षेत्र के लिए वर्ष 2020-2021 से 2022-2023 की अवधि के लिए 500 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। वर्ष **2020-21 और 2021-22** के दौरान अब तक एनबीएचएम के तहत वित्त पोषण हेतु लगभग **139.23** करोड़ रुपये की सहायता प्रदान करते हुए **114** परियोजनाएं अनुमोदित/स्वीकृत की गई हैं।

11. कृषि यंत्रीकरण

कृषि को आधुनिक बनाने और कृषि कार्यों में कठोर श्रम को कम करने के लिए कृषि यंत्रीकरण अत्यंत महत्वपूर्ण है। वर्ष 2014-15 से मार्च, 2022 की अवधि के दौरान कृषि यंत्रीकरण के लिए 5490.82 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है। किसानों को राजसहायता आधार पर 13,88,314 मशीनें और उपकरण प्रदान किए गए हैं। किसानों को किराये पर कृषि मशीनें और उपकरण उपलब्ध कराने के लिए 18,824 कस्टम हायरिंग केंद्र, 403 हाई-टेक हब और 16,791 फार्म मशीनरी बैंक स्थापित किए गए हैं। वर्तमान

वर्ष अर्थात 2022-23 के दौरान अब तक राजसहायता पर लगभग 65302 मशीनों के वितरण, 2804 सीएचसी, 12 हाईटेक हब और 1260 ग्राम स्तरीय फार्म मशीनरी बैंकों की स्थापना के लिए 504.43 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है।

12.किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड उपलब्ध कराना

पोषक तत्वों के ईष्टतम उपयोग के लिए वर्ष 2014-15 में मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना शुरू की गई थी। किसानों को निम्नलिखित संख्या में कार्ड जारी किए गए हैं।

(i) चक्र-I (2015 से 2017) - 10.74 करोड़
(ii) चक्र-।। (2017 से 2019) - 12.19 करोड़
(iii) मॉडल ग्राम कार्यक्रम (2019-20) - 23.71 लाख
(iv) वर्ष 2020-21 में- 11.52 लाख

13.**राष्ट्रीय कृषि मंडी (ई-नाम) विस्तार प्लेटफार्म की स्थापना करना**

(i) 22 राज्यों और 03 संघ राज्य क्षेत्रों की 1260 मंडियों को ई-नाम प्लेटफार्म से जोड़ा गया है।
(ii) दिनांक 29.11.2022 तक की स्थिति के अनुसार, ई-नाम पोर्टल पर 1.74 करोड़ से अधिक किसानों और 2.37 लाख व्यापारियों को पंजीकृत किया गया है।
(iii) दिनांक 29.11.2022 तक की स्थिति के अनुसार, ई-नाम प्लेटफॉर्म पर लगभग 2.33 लाख करोड़ रूपए के मूल्य वाली कुल 6.8 करोड़ मीट्रिक टन मात्रा व 20.05 करोड़ (बांस, पान के पत्ते, नारियल, नींबू और स्वीट कॉर्न) का सामूहिक रूप से व्यापार दर्ज किया गया है।
(iv) दिनांक 01.12.2022 की स्थिति के अनुसार ई-नाम प्लेटफॉर्म पर मूल्यांकन करने के लिए 203 कृषि एवं संबद्ध उत्पादों के लिए व्यापारी योग्य मापदंड बनाए गए हैं।

14.राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन - ऑयल पाम - एनएमईओ के शुभारंभ को 11,040 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ अनुमोदित किया गया है। इससे अगले 5 वर्षों में पूर्वोत्तर राज्यों में 3.28 लाख हेक्टेयर और शेष भारत में 3.22 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में ऑयल पाम वृक्षारोपण के तहत 6.5 लाख हेक्टेयर का अतिरिक्त क्षेत्र शामिल किया जाएगा। यह मिशन उद्योग द्वारा सुनिश्चित खरीद से जुड़े किसानों को सरल मूल्य निर्धारण सूत्र के साथ ताजे फलों के गुच्छों (एफएफबी) के व्यवहारिक मूल्य प्रदान करने पर केंद्रित है।

15.कृषि अवसंरचना कोष (एआईएफ)

वर्ष 2020 में एआईएफ की स्थापना के बाद से, इस योजना ने 19191 से अधिक परियोजनाओं के लिए देश में 14170 करोड़ रुपये के कृषि बुनियादी ढांचे को मंजूरी दी है।

इस योजना की सहायता से विभिन्न कृषि अवसंरचनाओं का सृजन किया गया है और कुछ अवसंरचना पूरी होने के अंतिम चरण में हैं। इन बुनियादी ढांचे में 8215 गोदाम, 3076 प्राथमिक प्रसंस्करण इकाइयां, 2123 कस्टम हायरिंग केंद्र, 992 छंटाई और ग्रेडिंग इकाइयां, 728 शीतागार परियोजनाएं, 163 परख इकाइयां और लगभग 3632 अन्य प्रकार की फसलोपरांत प्रबंधन परियोजनाएं तथा सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियां शामिल हैं।

16.कृषि उपज संभाररततंत्र में सुधार, किसान रेल की शुरूआत।

रेल मंत्रालय द्वारा विशेष रूप से जल्द खराब होने वाली कृषि वस्तुओं की आवाजाही को सुगम बनाने के लिए किसान रेल शुरू की गई है। पहली किसान रेल जुलाई, 2020 में शुरू की गई थी। दिनांक 31 दिसंबर, 2022 तक 167 मार्गों पर 2359 किसान रेल सेवाएं संचालित की गई हैं।

17.एमआईडीएच - क्लस्टर विकास कार्यक्रम:

क्लस्टर विकास कार्यक्रम (सीडीपी) को बागवानी समूहों की भौगोलिक विशेषज्ञता का लाभ उठाने और उत्पादन पूर्व, उत्पादन, फसल कटाई के बाद, रसद, ब्रांडिंग और विपणन गतिविधियों के एकीकृत और बाजार-आधारित विकास को बढ़ावा देने के लिए तैयार किया गया है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय (डीएएंडएफडब्ल्यू) ने 55 बागवानी समूहों की पहचान की है, जिनमें से 12 को सीडीपी के प्रायोगिक चरण के लिए चुना गया है।

18.कृषि और संबद्ध क्षेत्र में स्टार्ट-अप व्यवस्था का निर्माण

अब तक, वित्त वर्ष 2019-20 से 2022-23 के दौरान डीएएंडएफडब्ल्यू के नालेज पार्टनर और कृषि व्यवसाय इनक्यूबेटरों द्वारा 1055 स्टार्टअप का अंतिम रूप से चयन किया गया है। डीएएंडएफडब्ल्यू द्वारा सहायता अनुदान सहायता के रूप में संबंधित ज्ञान साझेदारों (केपी) और आरकेवीवाई-रफ्तार कृषि व्यवसाय इंक्यूबेटर (आर-एबीआई) को इन स्टार्टअप के वित्त पोषण के लिए 66.83 करोड़ रुपये की अनुदान सहायता जारी की गई है।

19.कृषि और संबद्ध कृषि-वस्तुओं के निर्यात में उपलब्धि

देश में कृषि और संबद्ध वस्तुओं के निर्यात में जोरदार वृद्धि देखी गई है। पिछले वर्ष 2020-21 की तुलना में, कृषि और संबद्ध क्षेत्र में निर्यात वर्ष 2020-21 **के 41.86** बिलियन अमरीकी डालर से बढ़कर वर्ष **2021-22 में 50.24** बिलियन अमरीकी डॉलर हो गया है अर्थात **19.99%** की वृद्धि हुई है।

रा.स.अता.प्र.सं.994

अनुबंध

2017-2021 के दौरान किसानों द्वारा राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार आत्महत्याएं

क्र.सं.	राज्यसंघ राज्य क्षेत्र/	2017	2018	2019	2020	2021
		किसान/ काश्तकार	किसान/ काश्तकार	किसान/ काश्तकार	किसान/ काश्तकार	किसान/ काश्तकार

1	आंध्र प्रदेश	375	365	628	564	481
2	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	1	0
3	असम	3	5	26	12	153
4	बिहार	0	0	0	0	0
5	छत्तीसगढ़	285	182	233	227	71
6	गोवा	0	0	0	0	0
7	गुजरात	4	21	3	5	0
8	हरियाणा	0	0	0	0	13
9	हिमाचल प्रदेश	4	5	12	6	13
10	झारखंड	0	0	0	0	0
11	कर्नाटक	1157	1365	1331	1072	1170
12	केरल	42	25	22	57	34
13	मध्य प्रदेश	429	303	142	235	117
14	महाराष्ट्र	2426	2239	2680	2567	2640
15	मणिपुर	0	2	0	1	0
16	मेघालय	0	0	0	4	3
17	मिजोरम	0	17	22	4	0
18	नागालैंड	0	0	0	0	1
19	ओडिशा	0	0	0	0	0
20	पंजाब	243	229	239	174	171
21	राजस्थान	3	2	2	0	0
22	सिक्किम	7	1	0	6	8
23	तमिलनाडु	19	6	6	79	61
24	तेलंगाना	846	900	491	466	352
25	त्रिपुरा	0	0	0	0	0
26	उत्तर प्रदेश	110	80	108	87	13
27	उत्तराखंड	0	0	0	0	0
28	पश्चिम बंगाल	0	0	0	0	0
29	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	2	4	5	6	2
30	चंडीगढ़	0	0	0	0	0
31	दादरा व नगर हवेली और दमन व दीव	0^{+}	7^{+}	7^{+}	$6^{@}$	$14^{@}$
32	केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली	0	0	0	0	0
33	जम्मू और कश्मीर	0^{*}	5^{*}	0^{*}	$0^{@}$	$1^{@}$
34	लद्दाख @	-	-	-	0	0
35	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0
36	पुदुचेरी	0	0	0	0	0
	कुल (अखिल भारतीय)	**5955**	**5763**	**5957**	**5579**	**5318**

राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार

'+' वर्ष 2018 और 2019 के दौरान पूर्ववर्ती दादरा व नगर हवेली और दमन व दीव यूटी का संयुक्त डेटा

'*' वर्ष 2018 और 2019 के दौरान लद्दाख सहित पूर्ववर्ती जम्मू व कश्मीर राज्य के आंकड़े

'@' नव निर्मित केंद्र शासित प्रदेश का डेटा

*****